सांख्यिकी और रिज़र्व बैंक : हाल के घटनाक्रम और परिदृश्य*

दीपक मोहंती

उप गवर्नर डा. ऊर्जित आर पटेल, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) के प्रभारी अधिकारी श्री ए.बी.चक्रवर्ती, केन्द्रीय कार्यालय विभागों के चयनित प्रधान, प्रख्यात सांख्यिकीविद् तथा शिक्षाजगत से आए अर्थशास्त्रीगण, तथा मित्रो! डीएसआईएम द्वारा आयोजित वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन 2013 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह सम्मेलन डीएसआईएम के अधिकारियों को एक मंच प्रदान करता है ताकि वे विशेषज्ञों के सामने अपने शोधपत्र प्रस्तुत कर सकें तथा नीति और अनुसंधान के लिए, विश्लेषण को और अधिक सार्थक बनाने हेतु, उनसे फीडबैक प्राप्त कर सकें। डीएसआईएम में मेरे सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न पर्चों पर चर्चा के लिए सहमति देने के लिए इन प्रख्यात प्रोफेसरों का मैं धन्यवाद करता हूँः प्रो. मनोज पंडा (निदेशक इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली), प्रो.एन. आर भानुमूर्ति, (एनआईपीएफपी, नई दिल्ली), प्रो.तथागत बन्द्योपाध्याय (आइआइएम, अहमदाबाद), प्रो.राजेंद्र वैद्य (आइजीआइडीआर, मुंबई), प्रो. चेतन घाटे (आईएसआई / आईसीआरआईईआर, दिल्ली), प्रो.पुलक घोष, (आइआइएम, बैंगलोर) तथा प्रो.टी.वी. रामनाथन, (पुणे यूनिवर्सिटी)। आप सब आर्थिक नीति निर्माण हेतु सांख्यिकीय शोध के सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र की बड़ी विशेषज्ञता और अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं, जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।

2. मैंने पहले भी कहा है कि सांख्यिकी एक सार्वजनिक हित की चीज़ है। एक केन्द्रीय बैंक के रूप में हमारी नीतियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों से इकट्ठी की गई विभिन्न वृहद् - वित्तीय सांख्यिकी जनरेट करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम ज्ञानाधारित नीति निर्माण में मदद के लिए सांख्यिकी और सांख्यिकीय टूल्ज़ का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। इसलिए एक अच्छा प्रायोगिक अर्थशास्त्री बनने के लिए एक मजबूत सांख्यिकीय ग्राउंडिंग, तथा आंकड़ों से निरंतर व्यवहार, मूल पूर्वापेक्षाएँ होती हैं। इस सम्मेलन में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति इसी बात की साक्षी है।

3. गत एक वर्ष में हुई सांख्यिकीय गतिविधियों में हुए प्रमुख घटना-क्रमों के आलोक में अब मैं संक्षेप में 2012 के सम्मेलन के परिणामों के बारे में सारांश में प्रस्तुत करूंगा। गत वर्ष के सम्मेलन में डीएसआईएम शोधकर्ताओं ने 12 तकनीकी पेपर्स प्रस्तुत किए। बाद में बाहरी विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, इन पेपर्स को पुनः संशोधित किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि इनमें से पांच पेपर्स रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर्स श्रृंखला रिज़र्व बैंक ओकेजनल पेपर्स, बाहरी जरनल्ज में प्रकाशन हेतु पहले से ही प्रस्तुत हो चुके हैं और अन्य पेपर्स पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं।

4. विभाग की शोध गतिविधियों में, आर्थिक संकेतकों का मापन, आर्थिक वृद्धि की मॉडलिंग तथा भविष्य कथन, मुद्रास्फीति कार्पोरेट कार्यनिष्पादन, तथा 'अग्र-दृष्टि-मौद्रिक नीति-निर्माण' हेतु प्रत्याशित बृहद् डिवेल्पमैंट्स, पर आर्थिक अभिकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं को जानना शामिल है। विभिन्न एकचर तथा बहुचर मॉडलों के आधार पर बृहद् और मुद्रास्फीति के प्रक्षेपित पथ को फैन चार्ट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में ''वृद्धि-मुद्रास्फीति'' समझौताकारी तालमेल (ट्रेडऑफ), विनिमय दर पास-थ्रू, तथा विभाग द्वारा चलाई गई मुद्रास्फीति परसिस्टेंस मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को विशेषीकृत करने के लिए विशेषरूप से लाभदायी रही है।

5. गत वर्ष सम्मेलन ने आँकड़ा निर्माताओं तथा प्रयोगकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और सहक्रिया बनाने के लिए बहुत से आँकड़ों और उनके प्रसार की पहल को रेखांकित किया। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटा बेस (डीबीआईई) नामक एक नया यूज़र फ्रैंडली इंटरफेस रिलीज़ किया है और आँकड़ा वेअरहाउस यूटीलिटीज़ को बैंक के एक प्रमुख उत्पादन टूल के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया है। अब बैंक के सभी सांख्यिकीय प्रकाशन तथा साथ ही आरबीआइ बुलिटेन तथा साप्ताहिक सांख्यिकीय सप्लीमेंट (डब्ल्यूएसएस) अब सीधे डीबीआइइ से जनरेट किए जा रहे हैं।

6. गत सम्मेलन में भी बैंकिंग आकड़ों में गुणवत्ता, कवरेज, प्रस्तुतीकरण तथा प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सुधार लाने के लिए नवप्रयास शुरू करने पर बल दिया गया था। चर्चा में

* 22 मार्च 2013 को मुंबई में आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती द्वारा दी गई प्रारंभिक टिप्पणियां

कहा गया था कि आँकड़ों की गुणवत्ता और कवरेज संबंधी मुद्दों पर विभिन्न विनियामक अनुसंधान तथा साथ ही नीति विभागों में तालमेल बिठाना जरूरी है, ताकि आँकड़ों की रिपोर्टिंग में सामञ्जस्य लाया जा सके। इस संबंध में विभाग ने इन मुद्दों पर चर्चा करने और इनका समाधान निकालने के लिए आरपीसीडी तथा डीवीएस के साथ वर्ष के दौरान परस्पर चर्चाओं के कई दौर चलाए। ग्रेन्यूलर स्तर पर जमाराशियों तथा ऋण संबंधी आँकड़ों की रिपोर्टिंग सामञ्जस्यपूर्ण बनाने के लिए बीएसआर प्रणाली के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वर्गीकरण और कोडिंग प्रणाली के अनुसार बैंकों की आँकड़ा संसाधन तथा रिपोर्टिंग प्रणालियों में, इनपुट आँकड़ा स्ट्रक्चर के कूटीकरण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इन सब आँकड़ों को बैंक के सीबीएस प्लेटफार्मों से स्रोतित करना है ताकि बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों को संसूचित आँकड़े बैंकों द्वारा रखे गए ग्रेन्यूलर आँकड़ा आधारों के समनुरूप हों। इन प्रयासों को और आगे ले जाने के लिए इस सम्मेलन में दो संरचित पैनल चर्चाएँ रखी गई हैं जिनमें बैंक के जोखिमधारक विभागों की सहभागिता है। आशा है कि आज तथा कल होने वाली चर्चाओं से, गुणवत्ता युक्त बैंकिंग सांख्यिकी की उपलब्धता के दरवाज़े खुलेंगे।

7. परिचालन मोर्चे पर विभाग ने 12 केन्द्रों में सिक्कों की मांग और उनके प्रयोग के संबंध में एक सर्वेक्षण किया। प्रचलन में आ रहे जाली नोटों के अनुमान पर एक शोधपत्र तैयार किया गया और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, जो सरकारी कारोबार का कार्य करते हैं, उनके एजेंसी कमीशन के एस्टीमेशन का सांख्यिकीय आधार प्रदान किया है।

8. विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण, विशेषकर वृहद् आर्थिक बदलावों से संबंधित सर्वेक्षण, अग्र दृष्टि वाली मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते रहे। ये सर्वेक्षण हैं: औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आइओएस), आदेश पुस्तकें, इन्वेंट्रीज तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस), क्रेडिट कन्डीशन्ज़ सर्वेक्षण (सीआरसीएस) घरों का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (आइईएसएच), उपभोक्ता कन्फीडेंस सर्वेक्षण (सीसीएस) तथा व्यावसायिक भविष्यकथनकारों का सर्वेक्षण (एसपीएफ)। इनमें से अधिकांश सर्वेक्षणों के निष्कर्ष अब प्रति तिमाही 'मेक्रो इकोनोमिक एंड मोनीटरी डिवेलपमैंट' तथा साथ ही रिज़र्व बैंक की साइट में एक साथ ही प्रकाशित किए जाते हैं। इससे हमारे सर्वेक्षण आउटपुट की दृश्यता में भी वृद्धि हुई और सर्वेक्षण परिणामों की 'प्रसार समयपरकता' में भी काफी सुधार आया है। तथापि इससे शोध निष्कर्षों की हमारी जिम्मेदारी तथा अच्छी गुणवत्ता की सांख्यिकी बनाकर रखने का हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ा है। हमारे सर्वेक्षण आंकड़ा विश्लेषण का तकनीकी कौशल, अब अन्तर्निहितत: सार्वजनिक समीक्षा के अंतर्गत आ गया है।

9. सर्वेक्षणों से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर दिशानिर्देशन के लिए सर्वेक्षणों पर एक उच्चस्तरीय तकनीकी परामर्श समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान आइइएसएच सर्वेक्षण को चारों केंद्रों में बढ़ा दिया गया है जिससे इसके अंतर्गत अब कुल 16 महत्त्वपूर्ण केंद्र शामिल हो चुके हैं। नए स्नातकों के रोज़गार अवसरों में प्रवृत्ति के आकलन के लिए 61 इन्जीनियरिंग तथा प्रबंध संस्थाओं से 2010-2011 तथा 2011-12 के प्लेसमैंट के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जून-अगस्त 2012 के दौरान 'तकनीकी संस्थाओं के फ्रैश स्नातकों के रोज़गार पर प्रायोगिक सर्वेक्षण' आयोजित किया गया। घर कीमत सूचकांक संकलन को भी चार और शहरों तक बढ़ा दिया गया है जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 10 नगर शामिल हो चुके हैं। इसके पूरक के रूप में बैंकों के पास उपलब्ध आवास ऋण खाता जानकारी के आधार पर विभाग ने सफलतापूर्वक आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) शुरू की है।

10. बैंक की वेबसाइट में 'ब्रांचलोकेटर' नामक एक गतिशील आंकड़ा आधार रिलीज़ किया गया है, जो कि वाणिज्य बैंकों की शाखाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी, (जैसे स्थान अवस्थिति तथा कारोबार का प्रकार) प्रदान की जाएगी। इससे बैंकों को शाखा विस्तार तथा वित्तीय समावेशन हेतु स्थानिक जानकारी तक पहुंचने में मदद मिली है। बीएसआर-4 सर्वेक्षण जो कि बैंक जमाराशियों के रूप में परिवारों की बचतों के अनुमान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया - रिज़र्व बैंक के प्रमुख सर्वेक्षणों में से एक है और जो कि अब तक नमूना आधार पर चलाया जाता था, अब इसे मार्च 2012 से एक जनगणना (सेन्सस) तक विस्तारित कर दिया गया है। मार्च 2012 की तिमाही से बीएसआर-7 का स्कोप भी बढ़ा कर, प्रकार (चालू, बचत, और सावधिक) के आधार पर, जमाराशियों का डाटा एकत्रित करने के लिए स्वरूपित किया गया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की बीआइएस कमेटी (सीजीएफएस) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आईबीएस में वृद्धियों को कार्यान्वित करने के लिए, एक स्थायी मॉनीटरिंग ग्रुप गठित किया गया है।

11. भारतमें मौद्रिक नीति संचारण, बैंकों के प्रभावी ऋण वितरण दर आंकड़ों के अभाव में, अवरोधित था। इस संदर्भ

में एक शोधपत्र में विभाग ने, व्यापक खाता स्तर बीएसआर आंकड़ा आधार पर आधारित, 1992-2010 की अवधि के लिए भारत के प्रमुख सेक्टरों हेतु, बैंक क्रेडिट के लिए भारित औसत ऋण वितरण दरों (डब्ल्यूएएलआर) पर तुलनीय वार्षिक समय श्रृंखला आंकड़े प्रदान किए हैं। इस जानकारी ने मौद्रिक संचालन के बैंक ऋण वितरण दर चैनल के अनुभवजन्य आकलन हेतु एक महत्त्वपूर्ण डाटा अंतराल को भरा है।

12. वर्तमान वृहद् आर्थिक परिदृश्य में वेतन कीमत स्पायरल, तथा मुद्रास्फीति का मुद्दा, फिर से उभर आया है और सार्वजनिक चर्चा का विषय बना रहा है। इस संदर्भ में विभाग ने ग्रामीण वेतन दर पर एक दीर्घकालिक श्रृंखला डाटा का समेकन किया है जो सभी प्रमुख राज्यों और साथ ही अखिल भारतीय स्तर के लिए 18 व्यवसायों हेतु श्रम ब्यूरो जरनल में निहित आंकड़ों पर आधारित है। यह जुलाई 1995 से लेकर नवंबर 2012 (नवीनतम) का मासिक आंकड़ा आधार है जो कि जनता के लिए डाटा वेयर हाउस में यूज़र फ्रेंडली फार्मेट में उपलब्ध है।

13. क्षेत्रीय बाज़ार की समझ अथवा सांख्यिकीय प्रबुद्धता, मौद्रिक नीति को महत्त्वपूर्ण इन्पुट्स प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाती है और कई केंद्रीय बैंकों ने क्षेत्रीय जानकारी इकट्ठी करने के लिए, सांख्यिकी प्रणाली स्थापित की है। प्रमुख केंद्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों की पुनर्गठित संरचना और व्यापक उपस्थिति से विभाग ने संबंधित आंकड़े और बाजार समझ एकत्रित करने की, इसी तरह की एक प्रणाली स्थापित की है, विशेषकर अनिवार्य पण्यों की कीमतों के क्षेत्र में। यह प्रणाली आधिकारिक आंकड़ों की रिलीज़ से पहले, पण्यों में कीमतों के दबाव को पहले से ही मापने के लिए, संभावित रूप से उपयोगी है। साथ ही ये आंकड़े डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई जैसे आधिकारिक मूल्य सूचकांकों में उपलब्ध मूल्य प्रवृत्तियों के वैधीकरण में भी लाभदायक हैं।

14. केंद्रीय बोर्ड के सुझाव के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देन, इलैक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटी-ईआरएस) के अंतर्गत, प्रयोजन कोड, छोटे प्राप्ति लेन-देनों सहित, सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों तक विस्तारित किया गया। इस परिणामकारी ट्रांज़िशन ने, बीओपी रिपोर्टिंग हेतु बीपीएम-6 मानकों का कार्यान्वयन करने वाले देशों में से एक बनने में भारत की मदद की। अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति, समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस), समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण (सीपीआइएस), (म्युच्युअल फंडों, बीमे तथा प्राइवेट कारपोरेट क्षेत्र के लिए) आइएमएफ के एसडीडीएस फ्रेमवर्क तथा जी-20 आँकड़ा अंतराल प्रयासों के अनुपालन में प्रतिबद्धता के एक अंश का ही प्रसार है।

15. वित्तीय आंकड़ों के मानकीकरण पर उच्चस्तरीय संचालन समिति (अध्यक्षः श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर) के अंतर्गत एक्सबीआरएल परियोजना ने वर्ष के दौरान काफी प्रगति की है। इस परियोजना के दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया है जिसमें 43 विवरणियां शमिल हैं (22 ओसमोस विवरिणयां, एफईडी तथा डीएसआईएम की 16 बाह्य क्षेत्र विवरणियां तथा यूबीडी की पांच विवरणियां)। एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग आंकड़ा वेयर हाउस के साथ एकीकृत की जा रही हैं, और यह यथा समय आने वाले सभी आंकड़ों के लिए प्राप्ति और वैधीकरण का एकमात्र प्लेटफॉर्म बन जाएगा।

16. केंद्रीय बैंकिंग आज इतनी चुनौती भरी हो गई है जितनी कभी नहीं रही, और समय पर तथा विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता प्रभावी नीति निर्माण की कुंजी है। रिज़र्व बैंक में सांख्यिकीविद् विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। यहां इस विभाग की बहुत सी उपलब्धियां रही हैं। अतः अब मैं विभाग के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को आपसे बांटना चाहूँगा।

सबसे पहले, बाज़ारों और संस्थाओं के विकास का अपरिहार्य परिणाम है- आंकड़ों में अंतराल। जैसा कि पिछले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटों से प्रकट हुआ है कि जब-जब समय पर और सही सूचना न मिलने के कारण प्रभावी रेस्पोंस करने की, नीति निर्माताओं और बाजार सहभागियों की, क्षमता में रुकावट आई है तब-तब ये अंतराल सामने आए है। वास्तव में हाल के इस संकट ने पुराने पाठ की पुनः पुष्टि की है कि अच्छे आंकड़े तथा अच्छा विश्लेषण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर प्रभावी निगरानी तथा नीतिगत प्रतिक्रियाओं के लिए जीवनाधार हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, जी-20 आंकड़ा अंतराल प्रयासों ने राष्ट्रों में एक ऐसा सांख्यिकीय ढांचा प्रदान किया है जो निरंतर तथा तुलनयोग्य है। डीएसआईएम चूंकि बैंक का माडल विभाग है इसलिए इस प्रयास को आगे बढ़ाने में इसकी प्रमुख भूमिका है।

दूसरे, वृहद् आर्थिक परिवर्तनों पर भी कुछ सर्वेक्षण हैं जो आगे और बल की मांग करते हैं। हमने नए स्नातकों के रोज़गार अवसरों के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने की एक शुरुआत की है। हमें अर्थव्यवस्था में संभावित मांग दबावों की बेहतर समझ होने की ज़रूरत है। इस

परिप्रेक्ष्य में एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है - खुदरा बिक्री, जो समग्र आर्थिक गतिविधि के शुरुआती संकेत प्रदान करती है। कई केंद्रीय बैंक, काफी प्रभावी ढंग से खुदरा बिक्री आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से नगरों में खुदरा बिक्री पर एक तिमाही सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए।

तीसरे, जहां विभाग ने ग्रामीण वेतन दर पर, आंकड़ा आधार विकसित किया है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी ''वेतन-कीमत-विकास'' को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए शहरी वेतन के समय श्रृंखला आँकड़े प्रदान करने के लिए तिमाही कार्पोरेट परिणामों की उपयुक्त रूप से जांच की जा सकती है।

चौथे, विभाग, रिज़र्व बैंक के भीतर और बाहर की विभिन्न समितियों में अपनी सहभागिता के ज़रिए, विभिन्न आंकड़ा अंतरालों तथा सांख्यिकीय मापन संबंधी मुद्दों पर भी कार्यरत है। एक खास मुद्दा जिसने हाल ही में फिर से ध्यान आकर्षित किया है वह है उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ) का विकास, जिसमें सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि यह सरकार द्वारा किया गया एक सांस्थानिक प्रयास है तथापि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पीपीआई के सांख्यिकी ढांचे से संबंधित कार्य विभाग द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।

पांचवें, गत पांच वर्षों के दौरान वित्तीय और बैंकिंग दोनों की सांख्यिकी प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन आए हैं। आंकड़ा समेकन तथा प्रसार के वैश्विक मानदंडों के अनुसार नई प्रणालियां शुरू की गई हैं। इस संदर्भ में बैंकिंग तथा वित्तीय सांख्यिकी मैन्युअल का अद्यतनीकरण करने के प्रयास किए जाने चाहिएँ, जो कि पिछली बार 2007 में प्रकाशित किया गया था।

छठवें, जहां मौद्रिक नीति निर्माण के लिए विभाग ने अग्र दृष्टि वाली जानकारी इकट्ठी करने के लिए काफी अंदर तक प्रयास किए हैं वहीं वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण पर हमारे प्रयास अभी सीमित हैं। वित्तीय समावेशन, बैंक की नीतिगत प्राथमिकता है। अतः विभाग के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं को वित्तीय समावेशन संबंधी सर्वेक्षणों को बनाने और उन्हें आयोजित करने के काम में लगाए खासकर बैंक के आउटरीच कार्यक्रम के अनुसरण में। गांवों के वित्तीय समावेशन पारिणामों के मूल्यांकन के संदर्भ में यह कार्य आरपीसीडी तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के तालमेल के साथ किया जाना चाहिए।

सातवें, विभाग की, केंद्रीय कार्यालय के कई विभागों में, महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है। जैसे मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी), बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ), आंतरिक कर्ज़ प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), भुगतान और निपटान प्रणालियां विभाग (डीपीएसएस), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), तथा वित्तीय स्थायित्व इकाई (एफएसयू)। यह वांछनीय है कि इन विभागों में हमारे अधिकारी, नीति और परिचालनात्मक मुद्दों के लिए, विश्लेषणात्मक इन्पुट्स प्रदान करें तथा शोध पत्र निकालें। ये पेपर्स सम्मेलनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अंततः आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला में प्रकाशित किए जा सकते हैं। इससे शोध, हमारे संघटनात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अधिक मूल्यवान साबित होगी।

आठवें, क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, विभिन्न इकाइयों में, शोध के प्रति केंद्रित और कटिबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले शोध एजेंडा को समयबद्धरीति से तैयार करने का कार्य पूरा किया जा सके। आंकड़ा प्रबंधन तथा प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का पूर्णतः प्रयोग किया जाना चाहिए। एक संपूर्ण भविष्यकथन प्रणाली तथा डीजीएसई मॉडेल्स विकसित करने के लिए मॉडलिंग तथा भविष्यकथन क्षमताओं को मजबूत करने की भी जरूरत है।

17. मैं अपने कथन का समापन, प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् जॉन टर्की की उक्ति से करना चाहता हूँ। सांख्यिकीविद् होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप हरेक के आंगन में खेल सकते हैं। मैं एक सांख्यिकीविद् के लिए असीम अवसर देख रहा हूँ क्योंकि जैसे-जैसे हम कई प्रश्नों से जूझते हैं, बैंक में सांख्यिकीय कौशल और सांख्यिकी की मांग बढ़ती ही रहती है। मुझे आशा है कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं से शिक्षा जगत और नीति निर्माता निकट आएंगे और सांख्यिकी विश्लेषण तथा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे। मैं संयोजन की सफलता के लिए हार्दिक कामना करता हूँ।

18. धन्यवाद् ।